फरीदाबाद

मज़दूर समाचार

दूनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

नई सीरीज नम्बर 87 सितम्बर 1995

अनिवार्य को, रुटीन को एक्सीडैन्ट कहते हैं! (3)

विश्व के चप्पे-चप्पे में रोज उठ रहे हैं सामुहिक कदम

★ **दफ्तर के बाहर गार्ड** : एक मैनेजर ने फैक्ट्री में अपने आफिस के बाहर गार्ड तैनात किया। मजदूरों को समूह में, ग्रुप में साहब के पास जाने से रोकना गार्ड की ड्युटी। गार्ड को हिदायत कि फैक्ट्री मैनेजर से मिलने आते मजदूरों के समूह को किसी लीडर को लाने को कहे और लीडर के आने पर उसके साथ सिर्फ एक मजदूर को साहब से मिलने दफ्तर के अन्दर जाने दे।

★ **"बिना लीडरों से पूछे कोई कदम नहीं उठायेगा"** : एक फैक्ट्री पर गेट मीटिंग में यूनियन लीडर दहाड़े कि लीडरों से पूछे बिना किसी डिपार्टमेन्ट के मजदूर संघर्ष करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

★ **"वरकर खुद ही बात करने लगेंगे तो हम लीडर क्या करेंगे"**: एक मजदूर के बच्चे बीमार थे। अपनी शिफ्ट बदलवाने के लिये वह परसनल मैनेजर के आफिस में गया। साहब के पास एक यूनियन लीडर बैठा था। वरकर के दफ्तर में प्रवेश करते ही लीडर गरम हो गया और उसे डाँटने लगा : मजदूर खुद ही अपने काम करने लगेंगे तो लीडरों की फिर जरुरत ही क्या रह जायेगी ; लीडरों को कोई क्यों पूछेगा ; हम लीडर क्या झख मारने के लिये बने हैं ...

★ **"साहब के सामने बड़ों-बड़ों की घिग्गी बन्ध जाती है"** : स्वामी रावण के तो दस सिर का ही किस्सा है, आधुनिक स्वामियों का आधुनिक प्रचारतन्त्र चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जी एम, डी सी, एस पी आदि-आदि के रौब-दाब, ज्ञान-हुनर, कुटिलता, शक्ति, पहुँच, क्रूरता आदि के ऐसे किस्से गढता है कि किसी भी बड़े साहब के सामने राम, रावण, कृष्ण, हनुमान, भीम, अफलातून, मोहम्मद, चाणक्य, चंगेज खान पानी भरते नजर आते हैं। दरअसल बड़े से बड़े साहब और आम मजदूर में व्यक्तिगत स्तर पर उन्नीस-बीस का फर्क होता है –– एक दायरे में साहब इक्कीस तो दूसरे दायरे में मजदूर इक्कीस।

झूठ के दबदबे के पक्षधर सत्यमेव जयते के ठप्पे दर ठप्पे लगाते हैं और मजदूरों के हर कदम पर लगाम लगाने वाले जनवाद के नगाड़े बजाते हैं...

नौकरी-नौकरी-नौकरी ! बचपना तक नौकरी के साँचे में ढाला जा रहा है – रोजगार की सीढी पर बचपने की बलि चढ रही है। नौकरी के लिये बाहुबल व बुद्धिबल ही नहीं बल्कि इस-उस के हाथ जोड़ना और लक्ष्मी की भेंट चढाना जरूरी तो बन ही गये हैं, यह सब अधिकाधिक अपर्याप्त भी होते जा रहे हैं। आमतौर पर मजदूर अकेले-अकेले करके भरती किये जाते हैं–– व्यक्ति स्वयं तथा उसके निकट जन इसके लिये पापड़ दर पापड़ बेलते हैं। भरती के लिये पूरी शिक्षा-दीक्षा ही प्रतियोगिता, व्यक्तिगत होड़ की है।

लेकिन...लेकिन **फैक्ट्री में, दफ्तर में भरती होते ही पूरी पढाई-लिखाई उलट जाती है**। टीम वर्क हर क्षेत्र में कार्य की आज अधिक से अधिक अनिवार्य आवश्यकता बनता जा रहा है। ऐसे में निजी सफलता की घुट्टी जहाँ तिकड़मबाजियों को जन्म देती है वहीं कार्यस्थल की हकीकत मिल-जुल कर कदम उठाने की ओर, सामुहिकता की तरफ धकेलती है। यह द्वन्द्व, निजी हित और सामुहिक हित के बीच खिंची लगती यह लक्ष्मण रेखा दरअसल विचार और व्यवहार (वास्तविकता) के बेमेल होने की अभिव्यक्ति है।

इस प्रकार, नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद व्यक्ति की पोजीशन जैसे बिलकुल बदल जाती हो वाली बात लगती है। यह किसी की मर्जी का सवाल नहीं है। फिर भी, मजदूरों को डराते-धमकाते समय मैनेजमेन्ट और लीडर नौकरी लगने से पहले के उनके हाथ जोड़ने के किस्सों तथा नौकरी से निकाल कर उन्हें फिर उसी स्थिति में धकेल देने की बातें खूब नमक-मिर्च लगा कर करते हैं। वैसे तथ्य यह है कि बेरोजगारों के लिये सामुहिकता कठिन होते हुये भी निरन्तर बढती बेरोजगारी का सिलसिला दुनियाँ-भर में जगह-जगह बेरोजगारों के बढती संख्या में सामुहिक कदमों को जन्म दे रहा है।

समूह में, टीम के तौर पर काम करवाना मैनेजमेन्टों की अनिवार्य आवश्यकता है। इसमें उनकी इच्छा-अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं है। **मैनेजमेन्टों की इच्छा तो यह रहती है कि मजदूर टीम रूप में काम करें पर टीम रूप मे व्यवहार नहीं करें** – जब कोई बात करनी हो तो वरकर अकेले-अकेल करके बात करने आयें।

लेकिन ... लेकिन ... लेकिन वास्तविकता में सामुहिकता का आधार अधिकाधिक घनिष्ट और व्यापक होता जा रहा है। प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसी हो गई है कि फैक्ट्री का चेन सिस्टम बढ कर फैक्ट्रियों के बीच चेन सिस्टम बन गया है। और, कम्प्युटरों-सैटेलाइटों का फैलता जाल दुनियाँ-भर के प्रोडक्शन प्रोसेसों तथा जीवन के अन्य पहलुओं को एक-दूसरे से अधिक से अधिक घनिष्टता से जोड़ रहा है। ऐसे में थोड़े से मजदूरों द्वारा मिल-जुल कर किसी मैनेजमेन्ट कि खिलाफ उठाये कदम का भारी और व्यापक असर पड़ता है। लन्च टाइम की डिमान्ड के सिलसिले में केल्विनेटर में 17 अगस्त को 22 कम्प्रेसर आपरेटरों द्वारा टूल डाउन स्ट्राइक करने से 4000 मजदूरों वाली फैक्ट्री में फ्रिजों का प्रोडक्शन जाम हो गया। अमरीका में एक रेलवे कम्पनी में मजदूरों द्वारा हड़ताल करने पर वहाँ की 40 रेलवे कम्पनियों को तालाबन्दी करनी पड़ी जिससे जनरल मोटर जैसी विशाल कम्पनियों की फैक्ट्रियों में दो दिन में प्रोडक्शन जाम होने लगा और अमरीका की संसद व राष्ट्रपति को इमरजैन्सी कानून लागू करने पड़े। फ्रान्स में पेरिस हवाई अड्डों के ग्राउन्ड वरकरों की हड़ताल ने यूरोप के पैमाने पर तत्काल असर डाला।

और, वर्तमान वास्तविकता की धुरी मार्केट के लिये प्रोडक्शन, मन्डी की होड़ है जो कि हर जगह वेतन कम करने - वर्क लोड बढाने की तरफ धकेलती है। ऐसे में मजदूरों में हर जगह असन्तोष का बढना लाजिमी होता है। मजदूरों का यह असन्तोष हर जगह और हर रोज मजदूरों द्वारा मिल-जुल कर मैनेजमेन्टों के खिलाफ छोटे-छोटे कदम उठाने के रूप में प्रकट होता है। जब-तब यह सामुहिक कदम बड़ा रूप भी धारण कर लेते हैं। **हर जगह और हर रोज मजदूरों द्वारा उठाये जाते छोटे सामुहिक**

(बाकी पेज तीन पर)

एक अध्यापक का पत्र

... मैं हरियाणा राज्य के एक राजकीय उच्च विद्यालय में एस. एस. मास्टर के पद पर पिछले बारह वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एम. ए., बी. एड. है।

अवस्था अड़तालिस वर्ष की है मगर लगता अठावन का हूँ। अगले दशक को पूरा कर पेन्शन प्राप्त करने से पूर्व मैं मुक्ति प्राप्त करने की तमन्ना रखता हूँ ताकि मेरी पत्नी को पेन्शन और पुत्र को सर्विस उत्तराधिकार में दे जाऊँ।

राष्ट्र निर्माता के इस पद की प्राप्ति के लिये मुझे अपने परिवार के तीन प्राणियों की आहूति दे कर स्वयं को बलि का बकरा बनाने के लिये बाध्य होना पड़ा है। यह कहानी मेरे एक अध्यापक मजदूर की कहानी न हो कर लाखों राष्ट्र निर्माताओं की कहानी है।

मेरा सौभाग्य यह है कि मैं पिछले बारह वर्ष से अपने निवास स्थान पर कार्यरत हूँ परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हजारों मण बोझे के तले दबा जा रहा हूँ। स्कूल का समय प्रात: आठ का है परन्तु उसके लिये छह बजे तो उठना अनिवार्य ही है।

पन्द्रह सौ बच्चों के बाप को आठ से दो तक चैन कहाँ। स्वीकृत तीस में से बीस पद वर्षों से खाली पड़े हैं। मानसिक तनाव में हिंसक बन कर बैंत का सहारा लेना पड़ता है। अन्य अधिकतर अध्यापक 20 से 30 किलोमीटर दूर से आने होते हैं तथा उन्हें डेढ वाली बस से जाना पड़ता है। बीच के समय में सुस्ताना, चाय पीना, अखबार पढना, गप्प-सप्प आदि आवश्यक बातें अनिवार्य हैं।

प्रत्येक कक्षा में 100 से 150 तक बालक-बालिकायें हैं और आठवीं कक्षा में तथा दसवीं कक्षा में बहुत से दूसरी, तीसरी व चौथी बार प्रविष्ट हुये हैं। पेचिदा बातों को न समझते हुये अध्यापक की तरफ बोतरू की तरह देखते हैं। यदि पूछा जाये कि बार-बार व्यर्थ में दाखिला लेने से क्या फायदा है तो उत्तर मिलता है, "शिक्षा बोर्ड की दुकान के ठेकेदार, सचिव व चेयरमैन बदल गये हैं और इस वर्ष चुनाव भी तो होना है —शायद बिद बैठ ज्या आर तुक्का लाग ज्या। उसके बाद लट्ठ बाज ज्या पाकस्तान तैं आर हम हो ज्यावाँ भरती फौज मँ।"

जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, वे बेचारी कुछ नहीं बोलती मगर अभिभावक कहते हैं, "अनपढ़ छोरी न कुण पुछै सै । दस जमात्य पढ़ ज्या तो नोकरी लाग्या छोरा मिल ज्या आर बिचारी का जीवन सुधर ज्या ।"

उपरोक्त कठिनाइयों भरे वातावरण के अतिरिक्त फार्म भरना, प्रमाण पत्र बनाना, प्रवेश देना - निष्कासन करना, सरकारी डाकों के जवाब देना ही खत्म नहीं होता। जब यह काम समाप्त हो जाये तो जनसंख्या शिक्षा के प्रशिक्षण कैम्प अटैण्ड करें, परिवार नियोजन के केस देवें, मतदाता सूचियाँ तैयार करें, फोटो पहचान पत्र बनवायें। निर्वाचनों का कार्य पंचायत स्तर से पार्लियामेन्ट स्तर तक सम्पन्न करवायें। जनगणना के आँकड़े तैयार करें।

क्योंकि आप राष्ट्र निर्माता हैं अत: इन कार्यों को बेगार न समझें और किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की बात न सोचें।

अब सुना है दोपहर के भोजन की व्यवस्था में व्यस्त भी होना पड़ेगा। पाँच अध्यापक 500 बच्चों को रोटियाँ बना कर खिलाया करेंगे।

पढाई की किसको फुरसत है और पढ कर क्या करना है। चारों तरफ निराशा ही निराशा है।

15 अगस्त 1995 — एक अध्यापक

रेमिंगटन रैण्ड

जीने को पैसा नहीं, मरने के लिये जहर नहीं

हम मजबूर हो कर यह पत्र लिख रहे हैं। रेमिंगटन रैण्ड को चलते हुये 21 वर्ष हो गये। जब हम इस कम्पनी में 1975 में लगे थे तो यह बहुत अच्छी लगती थी और थी भी : काम करने में जी लगता था, ओवर टाइम रोज तो रोज — इतवार छुट्टी वाले दिन भी होता था, तनख्वाह उसी महीने की 27 तारीख को मिलती थी, इन्सैन्टिव मिलता था, हाथ धोने को टायलेट में शैम्पू होता था, बोनस 20 प्रतिशत मिलता था, कैन्टीन बहुत अच्छी हुआ करती थी, स्पोर्ट्स के लिये हर फेसीलिटी थी, रैस्ट रूम हुआ करता था। कोई विजिटर मिलने आता तो उसे रिसेप्शन में बिठाया जाता था, किसी कर्मचारी का अगर फोन आये तो इन्टरफोन से बुलाया जाता था। कम्पनी तो इन्टरनेशनल थी। परन्तु आज इन सब का उल्टा है। काम में जी नहीं लगता, तनख्वाह का कोई दिन-तारीख फिक्स नहीं। उसी महीने की 27 की बजाय लीडरों ने पैसा खा कर अगले महीने की 7 तारीख करवा दी परन्तु इन लीडरों से, इन मैनेजमेन्ट के दल्लों से कोई पूछ नहीं सकता कि इनकी 7 तारीख को भी सेलरी क्यों नहीं मिलती। 15, 16, 17 या 18 तारीख तक सेलरी का आँख फाड़-फाड़ कर इन्तजार करना पड़ता है। ओवर टाइम बन्द है। हाथ धोने को शैम्पू तो भूल जाओ, साबुन के टुकड़ों को तरसते हैं। बोनस को नहीं मिले चार वर्ष पूरे हो गये हैं और अब पाँचवा वर्ष लगा हुआ है — बोनस का कोई अता-पता नहीं है। कैन्टीन को लीडरों और मैनेजमेन्ट ने मिलीभगत से बन्द कर दिया है। स्पोर्ट्स का जो भी सामान टूटता गया वह कबाड़े में बिक गया, बाकी पर जिस लीडर की नजर पड़ी वह सामान लीडरों के घरों में अभी भी मौजूद है। रैस्ट रूम को स्क्रैप रूम बना दिया गया, जितना स्क्रैप था रैस्ट रूम में भर दिया गया। अब कोई विजिटर मिलने आता है तो गेट से बाहर खड़ा रहे चाहे धूप हो या बारिश — चाहे किसी कर्मचारी का बीमार बाप ही क्यों न आया हो। किसी कर्मचारी का अगर फोन रिसेप्शन में आ जाये तो इन्टरफोन सारे प्लान्ट में खराब पड़े हैं। रिसेप्शनिस्ट...

हाँ, हमारे इतने प्यारे, आँखों के तारे लीडरों को और कुछ ना मिला तो फिर मैनेजमेन्ट से एग्रीमेन्ट क्यों किया ? अपनी जेब भरने के बाद सरकार की तरफ से मँहगाई भत्ता आता है वह भी इन दल्ले लीडरों ने साँठ-गाँठ करके सील करवा दिया। चार साल से मँहगाई भत्ता ना मिलने के कारण अब वरकर ना जी सकते हैं और ना मर सकते हैं। आजकल 1200 या 1500 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है ? मकान का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, किताबें, कापियाँ, ड्रेस, बीमारी, रिश्तेदारी, आना-जाना, दूध का बिल, राशन का बिल आदि इस मँहगाई के कारण अब जीना मुश्किल हो गया है। इस 1200 रुपये में हमारा तो क्या किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। पहले डी. ए. से कुछ न कुछ हर तीन महीने में तनख्वाह बढती रहती थी परन्तु महँगाई भत्ता सील करने से अब पाँच वर्ष से इसी तनख्वा में रेमिंगटन का मजदूर पिस रहा है। हर महीने गुजारा न होने पर मजबूर मजदूर 5 से 10 प्रतिशत प्रतिमाह {यानि 60 से 120 प्रतिशत वार्षिक ब्याज} पर कर्ज उठाता है। कर्जा देने वाले हर तनख्वा वाले दिन 5 या 10 प्रतिशत गला पकड़ कर वसूल लेते हैं। तनख्वा से क्या-क्या करें ? अब हम रेमिंगटन के बारे में और क्या लिखें ? हर जगह भ्रष्टाचार ! कम्पनी में कोऑपरेटिव सोसायटी चल रही है। जिस मेम्बर को लोन लेना है वह एक बोतल शराब 5000 रुपये लोन पर और 10,000 लोन पर पूरे कोपॅरेटिव के संचालकों को मीट-शराब के साथ न्यौता दे। न्यौते में खर्च के बाद लोन लेने वाले के 8000 रुपये पल्ले पड़ते हैं। बताओ है नो सतयुग — 8000 रुपये ले कर साइन करो 10,000 पर और उसकी किस्त व इन्टरैस्ट भरते रहो तथा हर महीने मरते रहो। रेमिंगटन का वह नाम जंचता है : ऊँची दुकान फीका पकवान।

30.8.95 — रेमिंगटन के दुखी कर्मचारी

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम

उ0 प्र0 सीमेन्ट निगम में लगभग एक हजार कैजुअल वरकर कार्य करते हैं। उनको प्रबन्धन द्वारा महीने में 20 दिन के आस-पास कार्य दिया जाता है। कोई सुविधा नहीं मिलती। अर्जित अवकाश सिर्फ लागू है, शेष सभी अवकाश नहीं मिलते। सभी कैजुअल श्रमिक सन् 1972 से लगातार कार्य कर रहे हैं, स्थाई नहीं किया है। आन्दोलन भी कई बार हुआ परन्तु प्रबन्धकों द्वारा यह बहाना बनाया जाता है कि श्रमिक अधिक हैं। श्रम विभाग भी ध्यान नहीं देता। कर्मचारियों की स्थिति काफी खराब है। प्रबन्धकों द्वारा वरकरों को जुलाई का वेतन 26 अगस्त तक भी नहीं दिया गया है। कैजुअल वरकर को त्योहारिक छुट्टी भी नहीं दी जाती।

26. 8. 95 — डाला सीमेन्ट फैक्ट्री का एक मजदूर

रुटीन ... सामुहिक कदम ... (पिज एक का बाकी)

कदमों को मैनेजमेन्टें आम चर्चा में नहीं आने देती, परन्तु इन पर मैनेजमेन्टों के रिसर्च संस्थानों में गम्भीरता से विचार किया जाता है। मजदूरों के चौंकाने वाले बड़े सामुहिक कदमों की प्रचारतन्त्र में चीर-फाड़ होती है पर उस चर्चा का सूत्र वाक्य है : यह एक्सीडैन्ट है। कानपुर में दस कपड़ा मिलों के 35 हजार मजदूरों द्वारा छँटनी रोकने के लिये रेलवे लाइनें जाम करने को एक अनहोनी, एक अजूबा कहा गया और उन्हीं मजदूरों के फिर लीडरों के चक्कर में आ कर बलि के बकरे बनने को सामान्य स्थिति करार दिया जाता है।

दरअसल, हकीकत में मिलजुल कर कदम उठाने के लिये बढता जा रहा आधार ही है जो कि मैनेजमेन्टों और सरकारों की सामुहिकता के अपहरण की जरूरतों को बढाता है। डिपार्टमेंट, शिफ्ट, पंचायत, युवा, स्त्री आदि-आदि की नुमाइन्दगी - लीडरी के वास्ते लीडरों का टिड्डीदल उनकी इस आवश्यकता की उपज है। सामुहिकता के अपहरण के इस सिलसिले में प्रतिनिधि पद्धति विकसित हुई है, चप्पे-चप्पे में फैल रही है, फैलाई जा रही है। लीडरी के लिये पार्टी-रूपी संस्थाओं के अधिकाधिक नाकारा होते जाने के साथ यह प्रयास विश्व बैंक - आई एम एफ सरीखों ने दुनियाँ-भर में काफी तेज कर दिये हैं। नुमाइन्दों के हाथों में लोगों की नकेल थमाने को यह प्रोपगेन्डा "जनता को सत्ता" देना कहता है।

और, मन्डी की होड़ का भारी-भरकम रोड़ रोलर मजदूरों के बीच की कैटेगरियों को कुचल कर सब को समतल कर रहा है, सब का कचूमर निकाल रहा है। गया वह दौर जहाँ परमानेन्ट होने का मतलब जीवन-भर नौकरी का सुरक्षित होना था। परमानेन्ट को सिकोड़ कर परिस्थितियाँ कैजुअल-परमानेन्ट-ठेकेदार के वरकरों को एक ही कैटेगरी में धकेल रही हैं। अधिक वेतन वाली फैक्ट्रियाँ बन्द हो रही हैं अथवा वेतन घटा रही हैं। अमरीका-जापान-जर्मनी में तनखायें घटाने के लिये भी फैक्ट्रियाँ मैक्सिको-भारत-फिलीपीन में लगाई जा रही हैं। मैनेजरों की छँटनी आम बात बनने की तरफ बढ रही है।

ऐसे में मजदूरों द्वारा जब-तब उठाये जाते बड़े पैमाने के सामुहिक कदमों के महत्व को तो समझने की जरूरत है ही, इससे भी **अधिक जरूरी है मजदूरों द्वारा आपस में सलाह-मशविरा कर खुद हर रोज और हर जगह उठाये जा रहे बहुत छोटे-छोटे कदमों के महत्व को समझने की।** मजदूरों द्वारा उठाये जाते छोटे-छोटे सामुहिक कदमों पर आम चर्चा इस दिशा में एक कदम है। वरकर आमतौर पर अपने इन कदमों की चर्चा नहीं करते। इससे इनके दौरान हासिल अनुभव - ज्ञान हमारी याददाश्त का हिस्सा नहीं बनता। यह घातक असर वाली बात है। रोज और हर जगह हमारे द्वारा उठाये जाते सामुहिक कदमों को नजरअन्दाज करने से लीडर-लीडरी की बन आती है और हमारा रोजमर्रा का व्यवहार हमारे विचारों में तरतीबवार ढँग से प्रतिबिम्बित नहीं होता। अपनी समझ, अपने निर्णय, अपने कदम यानि, बहुत छोटे-छोटे सामुहिक कदम जो हर जगह और रोज उठते हैं वे आपस में जुड़ जायें तो? हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार के अनुसार अपने विचार बना कर लीडर-लीडरी को ठुकराना शुरु कर दें तो?

"ऐसे में तो कोई कम्पनी, कोई सरकार चल ही नहीं सकेगी।" जी हाँ, बिलकुल ठीक बात है। नेता-मन्त्री-सन्त्री-अफसर-चेयरमैन वाला तन्त्र जो कि हमारे लिये जलालत और बदहाली का जीवन लिये है वह ध्वस्त हो जायेगा-- इसके लिये हमें कोई अफसोस नहीं है, नहीं होगा। हमारे रोज और हर जगह उठ रहे छोटे-छोटे सामुहिक कदम नये समाज का आधार लिये हैं। आपस में जुड़ कर हमारे यह छोटे-छोटे कदम विश्वव्यापी समता वाले समाज, बराबरी वाले समाज की रचना कर सकते हैं। हमें किन्हीं नये मानवों की जरूरत नहीं है और न हीं हमें किसी महामानव की आवश्यकता है। वर्तमान के ही अपने समूह बल और सामुहिकता के मेल द्वारा मजदूर काम के पहाड़ को पलट सकते हैं।■

सोने की जगह सुहागा

भारत गोल्ड माइन्स मजदूरों द्वारा सामुहिक कदम उठा कर 23 दिन हड़ताल

कर्नाटक राज्य स्थित कोलार सोना खदानों में 115 साल से मजदूर लगा कर सोना निकाला जा रहा है। यह खदानें केन्द्र सरकार की कम्पनी, भारत गोल्ड माइन्स लमिटेड की हैं। काँग्रेस, भा ज पा, सी पी आई, सी पी एम, जनता दल, रिपब्लिकन पार्टी आदि-आदि से जुड़ी 17 यूनियनें हैं। जयराज नाम के एक मजदूर के अनुसार यूनियनें शुरु से ही हैं पर उन्होंने शायद ही कभी मजदूरों के हित में काम किया है, यूनियनें अपने ही फायदे की धन्धेबाजी में व्यस्त रहती हैं। सोना खदान मजदूरों में सशक्त धारणा है कि चन्दा लेने के अलावा यूनियनों को आम मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। यूनियनों की हमदर्दी मैनेजमेन्ट के साथ है और वे सदा ही मैनेजमेन्ट की कठिनाइयों को "समझने" को तैयार रहती हैं। मैनेजमेन्ट ने कई खदानें बन्द कर दी पर यूनियनों ने कुछ नहीं किया। सरकारों की तरह भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को बी आई एफ आर ने बीमार घोषित किया हुआ है। चार साल से मजदूरों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई।

लाल-पीली-नीली-काली-तिरंगी-पंचरंगी 17 यूनियनों को एक तरफ छोड़ कर कोलार सोना खदानों के 6500 मजदूरों ने आपस में विचार-विमर्श किया और 2 अगस्त को हड़ताल शुरू कर दी। "बिना लीडरों के नहीं चलेगी"-- 17 यूनियनें बन्दर की तरह पँच बन कर टुकड़ों के चक्कर में टकटकी लगा कर बैठ गई। मैनेजमेन्ट साम-दाम-दण्ड-भेद की पुश्तैनी नीति पर अमल शुरू कर हड़ताल को शीघ्र ही तोड़ देने के प्रति आश्वस्त थी।

6500 सोना खदान मजदूरों ने मैनेजमेन्ट और 17 यूनियनों की आशा पर पानी फेर दिया। आपस में विचार-विमर्श करते हुये, स्वयं फैसले करते हुये 6500 मजदूरों ने सफलता से हड़ताल को जारी रखा। स्ट्राइक को 20 दिन से ऊपर होगये तब सरकार और मैनेजमेन्ट को परेशानी होने लगी। कम्पनी बीमार है आदि-आदि कठिनाइयाँ धरी रह गयी और हड़ताल के 23 वें दिन प्रत्येक मजदूर को 4000 रुपये एकमुश्त एक्सग्रेसिया तथा सितम्बर से वेतन में 50 रुपये अन्तरिम वृद्धि के लिये सहमत हो कर सरकार व मैनेजमेन्ट ने स्ट्राइक खत्म करवाई। 2 अगस्त से 25 अगस्त तक भारत गोल्ड माइन्स के 6500 मजदूरों ने शानदार सामुहिक कदम उठा कर एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। केन्द्र सरकार और मैनेजमेन्ट के लिये किसी सोना खदान को बन्द करना तथा मजदूरों की छँटनी करना अब बहुत मुश्किल काम होगा।■

(जानकारी हमने 31 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स से ली है।)

पट्टी और नकेल (पिज चार का शेष)

उन्हें ड्युटी पर लेने को मजबूर किया था।

लगता है कि ईस्ट इंडिया मैनेजमेन्ट ने सूई खूब डूँगी-गहरी गड़ा कर यह टैस्ट किया है कि मजदूरों की आँखों पर नई पट्टी और नई नकेल कारगर हैं कि नहीं। अब मैनेजमेन्ट को मात्र यह करना है कि नये लीडरों से सौदा पटा ले।

अदालत में तनखा के लिये केस...ईस्ट इंडिया की ही 1983 में बन्द की गई जूट मिल के 900 मजदूरों का हिसाब का पैसा अदालती भँवर में 12 साल से गायब है। नये चुनाव की डुगडुगी...मान्यता के लिये प्रयास होंगे...

लगता है कि ईस्ट इंडिया में 1979 जैसी परिस्थितियाँ फिर बन रही हैं। आँखों पर पट्टी और नकेल पर मजदूरों की सहमती ने तब दो-ढाई हजार मजदूरों की छँटनी पर पर्दा डालना मैनेजमेन्ट के लिये आसान बनाया था।

दस हजार की बजाय इस बार भी हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट रहे हैं। दो हजार मजदूर अगर हर महीने दो-दो रुपये दें तो पहले की तरह दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

एस्कोर्ट्स नोन-मैनेजेरियल स्टाफ

फरीदाबाद में एस्कोर्ट्स की 14 फैक्ट्रियों के 3200 इंजिनियरों, सेल्स अफसरों, परचेज अफसरों, अकाउन्ट्स अफसरों आदि ने एस्कोर्ट्स की सूरजपुर, पटियाला व बंगलौर फैक्ट्रियों और अन्य शहरों में दफ्तरों में कार्यरत अपने सहकर्मियों के साथ मिल कर मैनेजमेन्ट के खिलाफ एक उल्लेखनीय आन्दोलन करके सफलता हासिल की है।

एस्कोर्ट्स के नोन-मैनेजेरियल स्टाफ ने दिसम्बर 94 में मैनेजमेन्ट से मजदूरों के समान प्रोडक्शन इनसेन्टिव डिमाण्ड किया। एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने हिसाब-किताब के नये वर्ष, यानि अप्रेल 95 में इस बारे में बातचीत करने की बात की। इस साल अप्रेल में मैनेजमेन्ट ने कहा कि जून में बात करेगी और फिर जून में कहा कि जुलाई में बात करेगी। अप्रेल और जून की तरह जुलाई निकलते देख फरीदाबाद स्थित एस्कोर्ट्स के 14 प्लान्टों के इंजिनियरों, सेल्स अफसरों, परचेज अफसरों, अकाउन्ट्स अफसरों आदि ने 25 जुलाई को हाफ डे की छुट्टी की और फस्ट प्लान्ट के गेट पर एकत्र हुये। वहाँ से 3200 का जलूस मथुरा रोड़ पर तीन मील रास्ता तय कर चेयरमैन को मेमोरेन्डम देने एस्कोर्ट्स कारपोरेट आफिस पहुँचा। जलूस के पहुँचने से पहले चेयरमैन खिसक लिया। तब कारपोरेट आफिस गेट पर जनरल बाडी मीटिंग हुई और अगले दिन से नियम अनुसार काम करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, भोजन भत्ते पर टैक्स के विरोध में कैन्टीनों में पुराने रेट से एक रुपया दस पैसे थाली के देने का भी फैसला किया।

नियम अनुसार काम करने पर एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने 31 जुलाई को चार को सस्पैन्ड कर दिया। इस पर पहली अगस्त को फरीदाबाद के 14 प्लान्टों में इंजिनियरों, सेल्स-परचेज-अकाउन्ट्स अफसरों ने हर प्लान्ट में वहाँ के मैनेजमेन्ट प्रमुख का घेराव किया। राजदूत मोटरसाइकिल प्लान्ट में घेराव को तोड़ने के लिये मैनेजमेन्ट ने रात साढे सात बजे फैक्ट्री में पुलिस बुलाई। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार करने पर सब गिरफ्तारी देने को आगे बढे और नारे लगाते हुये पुलिस ट्रक की तरफ चले। तब 12 घन्टे से घेराव में फँसा चीफ वहाँ से भागा और फिर पुलिस भी किसी को गिरफ्तार किये बिना फैक्ट्री से चली गई।

एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने पहली अगस्त को 10 और सस्पैन्ड कर दिये तथा "काम नहीं, वेतन नहीं" के नोटिस टाँग दिये। फरीदाबाद के 14 प्लान्टों के साथ ही सूरजपुर, पटियाला व बंगलौर प्लान्टों तथा अन्य जगह दफ्तरों में नोन-मैनेजेरियल स्टाफ ने टूल डाउन हड़ताल शुरु कर दी। 2 अगस्त से हर जगह तीनों शिफ्टों के हड़ताली इंजिनियर आदि सुबह की शिफ्ट में इक्ट्ठे आने लगे और उपस्थिति दर्ज कर अपने-अपने प्लान्ट में एक स्थान पर इक्ट्ठे बैठने लगे। इसके अलावा संयुक्त मीटिंगें होती रही और हर मीटिंग में उपस्थिति प्रभावशाली रही। 12 अगस्त को एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट के पीछे ग्राउन्ड में खुले में जनरल बाडी मीटिंग भारी बरसात के बीच जारी रही और 3200 इंजिनियर, सेल्स - परचेज - अकाउन्ट्स अफसर ढाई घन्टे स्वतन्त्रता से विचार-विमर्श करते रहे।

ऑल एस्कोर्ट्स इम्पलाइज यूनियन के प्रेसीडेन्ट को ही ऑल एस्कोर्ट्स नोन-मैनेजेरियल स्टाफ एसोसियेशन ने अपना प्रेसीडेन्ट बनाया था पर वह हड़तालियों की एक भी मीटिंग में नहीं आये। समर्थन तो रहा दूर की बात, प्रेसीडेन्ट ने विरोध ही किया। टॉप मैनेजमेन्ट तो एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठती है और रोज की चिक-चिक मजदूरों तथा सुपरवाइजरी स्टाफ में होती है। हड़ताल के समय एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट और यूनियन लीडरों ने मजदूरों को भड़काने की खूब कोशिशें की फिर भी आमतौर पर मजदूरों की हमदर्दी हड़ताली इंजिनियरों, सेल्स-परचेज-अकाउन्ट्स अफसरों के साथ थी। प्रोडक्शन सामान्य से आधे से भी कम हो गया। सप्लायरों की बन आई और घटिया मैटेरियल सप्लाई किया। इस पर कुछ डीलरों ने डेलीवरी लेने से इनकार कर दिया — मोटरसाइकिलों से भरे ट्रक लौटा दिये गये।

और, हड़ताल मजबूती से जारी रही। 21 अगस्त को एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट के गेट पर इक्ट्ठे हो कर 3200 हड़तालियों का जलूस डी सी आफिस गया। डी सी वहाँ नहीं थे। वहीं पर मीटिंग में निर्णय लिया गया कि टूल डाउन स्ट्राइक को जारी रखने के साथ-साथ अगले दिन, 22 अगस्त से एस्कोर्ट्स कारपोरेट आफिस के गेट पर भूख हड़ताल शुरु की जाये।

21 अगस्त की रात को चेयरमैन ने हड़तालियों से बातचीत की। प्रोडक्शन इनसैन्टिव की जगह परफारमेन्स अलाउन्स नाम से पैसे देने, भोजन भत्ते को टैक्स फ्री करने और सस्पैन्ड लोगों को हफ्ते-भर में ड्युटी पर लेने के प्रस्ताव चेयरमैन ने रखे। 22 अगस्त को सुबह हड़तालियों की जनरल बाडी मीटिंग में मैनेजमेन्ट की पेशकश स्वीकार की गई और 11 बजे इंजिनियरों, सेल्स-परचेज-अकाउन्ट्स अफसरों ने 22 दिन से जारी हड़ताल खत्म की।■

19 सितम्बर को सुबह दस बजे, 20 को शाम 5 बजे और 21 सितम्बर को रात 8 बजे इस अखबार के सितम्बर अंक पर मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा होगी। हर कोई इसमें भाग ले सकता है।

ताकत और कमजोरी

लन्च टाइम की डिमान्ड के लिये मैनेजमेन्ट से चल रही उठा-पटक के सिलसिले में मात्र 22 कम्प्रेसर आपरेटरों ने 17 अगस्त को टूल डाउन स्ट्राइक कर केल्विनेटर के तीन प्लान्टों मे प्रोडक्शन जाम कर दिया। 4000 मजदूरों में से 150-200 ही छुट-पुट काम करते रह सके। आज प्रोडक्शन प्रोसेस में चेन सिस्टम की वजह से थोड़े से मजदूरों द्वारा उठाये कदम की विशाल शक्ति का यह एक बढिया उदाहरण था।

18 को छुट्टी। 19 को मैनेजरों ने खुद आधे घन्टे तक कम्प्रेसरों को चला कर 40-50 फ्रिज बनवाये। 20 की छुट्टी। 21 को प्रोडक्शन जाम। 22 को भी, 23 को भी जाम ... साहबों के साहब ने स्वयं हस्तक्षेप करके बला टाली। 23 अगस्त को दो बजे से 22 कम्प्रेसर आपरेटरों ने काम शुरू किया तब केल्विनेटर में 4000 मजदूरों की प्रोडक्शन लाइन शुरू हुई।

केल्विनेटर को वर्लपूल यानि डुबो देने वाली भँवर का नया नाम दे रही मैनेजमेन्ट इस घटनाक्रम से हिल गई थी परन्तु केल्विनेटर के मजदूर अपनी ताकत के इस रूप से बेखबर थे। कम्प्रेसर आपरेटरों के अलावा केल्विनेटर के जिन भी वरकरों से हमने बात की वे मामले से अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं मानते थे। मजदूरों के लिये अत्यन्त महत्व की इस घटना का मूल्याँकन करने की जरूरत ही महसूस नहीं की जा रही थी। यह कमजोरी ही है कि प्रोडक्शन जाम के दौरान के वेतन की कोई चर्चा नहीं और लीडर लोग नई एग्रीमेन्ट में फच्चर के तौर पर ही कम्प्रेसर आपरेटरों के कदम को पेश कर सके।■

पट्टी और नकेल

ईस्ट इंडिया कॉटन मिल में जुलाई के आरम्भ में की गई दस दिन की तालाबन्दी के दौरान इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हरियाणा सरकार के एक मन्त्री ने मजदूरों के बीच बढ-चढ कर भाषण दिये और नये लीडरों ने मन्त्री की खूब जयजयकार करवाई। पुलिस ने मजदूरों को जबरन फैक्ट्री से निकाल कर और फैक्ट्री गेट से खदेड़ कर तालाबन्दी करने में मैनेजमेन्ट की मदद की थी परन्तु प्रचार किया गया कि मंत्री साहब के कारण पुलिस व प्रशासन मजदूरों की मदद कर रहा है। कहा गया कि मंत्री जी दबाव डाल कर तालाबन्दी खत्म करवा रहे हैं। मंत्री की चुनावी तैयारी के सिलसिले में हुई मीटिंग में नये लीडर ईस्ट इंडिया मजदूरों का जलूस ले गये जिससे वह विशाल और कामयाब मीटिंग हो गई। मंत्री ने भाषण में कहा कि दस दिन की तालाबन्दी के पैसे मजदूरों को देने का फैसला हुआ है।

आठ-दस अगस्त को जुलाई वेतन के समय मजदूरों को पता चला कि मैनेजमेन्ट ने दस दिन की तालाबन्दी के और आठ दिन काम किये के पैसे सजा के तौर पर काट लिये हैं। 18 दिन का वेतन काट लेने पर फैक्ट्री जाम नहीं हुई; मंत्री के घर मुर्दाबाद के नारे लगाता जलूस नहीं गया — इसलिये कि नये लीडरों ने ऐसा करने को नहीं कहा। जून में जब मजदूरों का किसी नेता में भ्रम नहीं था, नकेल किन्हीं लीडरों के हाथों में नहीं सौंपी थी तब 5 वरकरों का गेट रोकने पर अजन्ता डिपार्टमेन्ट वरकरों ने चक्का जाम करके मैनेजमेन्ट को उसी दिन

(बाकी पेज तीन पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी-548 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।
RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73